

भारत नमन

भारत सरकार (डीएवीपी) एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त

वर्ष:23 अंक: 13 देहरादून, सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025 nareshrohilla18@gmail.com प्रति मूल्य: 1 रूपया वार्षिक : 50 रू

उत्तराखंड को विश्व बैंक से मिलेंगे 680 करोड

देहरादून(भारत नमन ब्यूरो)। उत्तराखंड सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में वित्तीय पादार्थित, उत्तरदायित्व और सेवा वितरण में सुधार के लिए राज्य को विश्व बैंक से 680 करोड रुपए का सहयोग मिलेगा। प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार ने इसकी सिफारिश की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने तथा सेवा प्रदाय व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्व बैंक से लगभग 680 करोड स्पए (लगभग 80मिलियन अमेरिकी डालर) की बाहय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक



मामलों के विभाग (एफबी प्रभाग) ने राज्य की इस महत्वकांक्षी परियोजना को विश्व बैंक के विचारार्थ अनुशंसित किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को विश्व बैंक भारत कार्यालय नई दिल्ली के कार्यवाहक कन्द्री

डायरेक्टर श्री पाल प्रसी को औपचारिक रूप से प्रेषित किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड सरकार के इस प्रस्ताव की प्रति संलग्न करते हुए इसे विचार एवं स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया जा रहा है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की वित्तीय प्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक आधुनिक, कुशल और पारदर्शी बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक तेजी, सटीकता और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके। परियोजना के तहत वित्तीय प्रबंधन, बजट नियंत्रण, लेखा प्रणाली, व्यय प्रबंधन और सेवा वितरण के क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार लागू किए जा सकें। मुख्यमंत्री धामी

ने व्यक्ति की प्रसन्नता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्र की इस अनुशंसा पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखंड के वित्तीय सुधार और सुशासन के प्रयासों की बड़ी स्वीकृति है। राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है कि प्रत्येक सरकारी रुपया जनता के हित में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ खर्च हो। विश्व बैंक की यह संभावित सहायता राज्य की वित्तीय प्रणालियों को डिजिटल, सुदृढ़ और परिणामोन्मुख बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से राज्य में राजकोपीय अनुशासन, वित्तीय डेटा पारदर्शिता, और सेवा प्रदाय तंत्र की गुणवत्ता में

अभूतपूर्व सुधार आएगा। प्रदेश के वित्त विभाग के अनुसार यह परियोजना राज्य की ई-गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को नई दिशा देगी। इससे राज्य के प्रत्येक विभाग में वित्तीय अनुशासन, रियल टाइम मानिट्रिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। यह पहल उत्तराखंड को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और उत्तरदायी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगी। केन्द्र सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य की वित्तीय प्रशासनिक संरचना को सशक्त बनाने के साथ साथ नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।

देहरादून रोजगार मेले में 215 युवाओं को नियुक्ति पत्र

देहरादून (भारत नमन ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्चुअल माध्यम से देश भर के 40 स्थानों पर करीब 51000 नवनि्युक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। देहरादून में सर्वे आफ इंडिया के आडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें उत्तराखंड डाक परिमंडल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्रीमती शशि शालिनी कुजुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर उत्तराखंड डाक विभाग में नियुक्त 59 डाक सहायकों एवं डाक सेवकों के अतिरिक्त रेलवे के 14, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 81, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 19, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के 41 एवं आईआईएम सिरमौर

के 1 सहित 215 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने सभी नवनि्युक्त युवाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने नवनि्युक्त युवाओं से आह्वान किया कि वे तत्परता एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएं। इस अवसर पर उत्तराखंड परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएं अनुसूया प्रसाद चमोला सहित रेलवे के अनिल कुमार सैनी, चीफ वेलफेयर आफिसर, केन्द्रीय सशस्त्र बल के अरविन्द खंडूरी, सहायक कमांडेंट आईटीबीपी, स्टेट बैंक के राजीव कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक, टीएचडीसी की मिस झरना दलाई, एवआर आफिसर एवं डाक विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।



स्थापना के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में मनाया जाएगा रजत जयंती समारोह

मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने तैयारियों को लेकर की अफसरों के साथ बैठक



देहरादून (एके विरमानी)। मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने सचिवालय में नवम्बर माह में प्रस्तावित प्रदेश के रजत जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन प्रदेश भर में किया जाए। बैठक के दौरान एक से 9 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी। मुख्य

सचिव ने कहा कि पिछले 25 सालों में राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं पर्यटन के साथ ही सडकों एवं नेटवर्क की कनेक्टिविटी में उपलब्धियों हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में पिछले 25 सालों की उपलब्धियों के साथ ही अगले 25 सालों का रोडमैप भी प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक नवम्बर से लेकर 09 नवम्बर तक प्रत्येक दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और इन कार्यक्रमों में श्रमिकों, किसानों

पूर्व सैनिकों तथा महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एल फौनई, आर मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, डा. पंकज कुमार पाण्डेय, डा. आर राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, डा. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, एवं धीरज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सम्पादकीय लोक लुभावन घोषणाएं

बिहार में विधानसभा चुनाव आ ही गया समझो। राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद नामांकन का काम लगभग समाप्त हो चला है और अब राजनीतिक दलों के वादों, इरादों और घोषणाओं का दौर चल निकला है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन पहले ही अपनी घोषणाओं को सामने रख चुका है और चुनाव से पहले ही पूरा करता दिख रहा है तो अब विपक्षी गठबंधन भी युवाओं के लिए कई लुभावनी योजनाएं देने को तत्पर दिख रहा है। इनमें हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जीविका दीदीयों को 30 हजार का वेतन, महिलाओं के लिए मुश्त योजना सहित स्वस्थ बीमा योजनाएं शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन योजनाओं में ही विपक्षी गठबंधन की जीत की चाबी छिपी है। वैसे बिहार के चुनाव में इस बार चाहे सत्तारूढ़ गठबंधन हो या विपक्ष सभी जनता को सब्जबाग दिखा रहे हैं। अगर यह कहा जाए कि बिहार में पैसा फेंको तमाशा देखो की तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री जदयू के नीतिश कुमार हैं। वे चुनाव से पहले ही प्रदेश के लाखों लोगों के लिए समाज कल्याण की कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। इनमें महिला रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं के खाते में 10 हजार की धनराशि तो सरकार ने भेजनी भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अभी तक 1.21 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गयी है। अगस्त 25 से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की योजना भी चल रही है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, युवा भत्ता, निर्माण श्रमिक वस्त्र भत्ता जैसी योजनाएं फिर से चुनाव जीतने पर लागू करने की घोषणाएं भी राजग गठबंधन के मुख्यमंत्री द्वारा की गयी। माना जा रहा है कि इनसे राजकोष पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। विपक्षी गठबंधन भी चुनाव जीतने के लिए ऐसी ही लोक लुभावन घोषणाओं को करते दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव तो सत्ता में आने पर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। विपक्ष की अन्य लोक योजनाओं की अपेक्षा हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का दांव वाकई बेहद बड़ा नजर आ रहा है। अगर परिवार के एक सदस्य के नौकरी दी जाती है तो करीब तीन करोड़ के आसपास नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। सत्ता में आने पर कोई सरकार ऐसा कर पाएगी या नहीं कह पाना मुश्किल है लेकिन युवाओं और खासकर नए युवा मतदाओं को यह योजना आकर्षित कर रही है। हालांकि विपक्ष की योजनाओं और घोषणाओं पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विशेष कर सत्तारूढ़ गठबंधन प्रश्न कर रहा है कि तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिन राज्यों में विपक्ष यानि कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां ऐसी योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू किया गया है। ऐसे ही बिहार में भी किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि जो योजनाएं बिहार के लिए घोषित की गयी हैं, उनका खाका जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा। चुनाव के बाद कौन या दल या गठबंधन सत्ता में आएगा, यह तो बाद में ही पता चलेगा लेकिन इतना अवश्य है फिलहाल वोट हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन हो या विपक्ष कोई कसर छोड़ता नहीं दिख रहा है। हर कोई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से धन देकर या लालच देकर अपनी जीत के लिए वोटों की खेती पका लेना चाहता है।

सीएम ने नंदानगर के आपदा पीड़ितों की यथासंभव मदद का दिया भरोसा



देहरादून(भारत नमन ब्यूरो)। चमोली जिले के नंदानगर प्रखंड में बीती 17 सितम्बर रात को आई भीषण आपदा से प्रभावित धुर्मा, सेरा, कुंतरी, फाली गांवों में हुई तबाही से पीड़ितों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शास्त्री और महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी के संयुक्त नेतृत्व में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सेवक सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर सीएम धामी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि वहां जनजीवन को पटरी पर वापस लाने के लिए महती प्रयास की आवश्यकता है। गौरतलब है कि 17 सितम्बर 2025 को धुर्मा गांव के ऊपर बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। लोगों के खेत खलिहान मोक्ष नदी की बाढ़ में बह गए थे, वहां कई आवासीय भवन, गौशाला बाढ़ की भेंट चढ़ गए थे जबकि खेत खलिहान, घराट, पनघट सब कुछ तबाह हो गया था। प्रशासन ने फौरी राहत पीड़ितों को पहुंचाई लेकिन

पुनर्निर्माण का मसला अभी तक लंबित है। फाली और कुंतरी गांवों में नौ लोग दब कर मर चुके हैं और कृषि भूमि के साथ अन्य परिसंपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। सीएम धामी खुद आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछने गए थे। तब उन्होंने स्वयं पीड़ितों को मदद पहुंचाई थी लेकिन प्रभावित लोगों की जिंदगी की अब शुरू हुई है। उनके खेत खलिहान सब बह गए थे। उनके पुनर्निर्माण की तात्कालिक और दीर्घकालीन आवश्यकता के मद्देनजर पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से आग्रह किया। प्रतिमंडल ने सीएम से कहा कि मोक्ष नदी के जलप्रवाह तंत्र को पूर्ववत करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। धुर्मा और सेरा गांव में मोक्ष नदी के प्रवाह क्षेत्र को पूर्ववत किए जाने की जरूरत है। इस पर मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी को तुरंत कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए। वर्ष 2023 में भी मोक्ष नदी ने रौद्र रूप दिखाते हुए सेरा गांव में तबाही मचाई थी। तब सिंचाई विभाग ने करीब पौने तीन करोड़

रुपए की लागत से तटबंध बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था किंतु उस प्रस्ताव की फाइल शासन में अटक रही। पत्रकारों ने सीएम से आग्रह किया कि इस बार पिछली बार की तरह चूक न हो, लिहाजा सेरा गांव में मोक्ष नदी पर तटबंध (चेकडैम) का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और प्रभावित गांवों में तबाह हुए खेत खलिहान और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को समय रहते किया जाए।

श्री धामी ने भरोसा दिलाया कि दैवीय आपदा पीड़ितों के साथ मदद के लिए सरकार खड़ी है। उन्हें भरसक मदद दी जाएगी। क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने इस पर संतोष जताया। प्रतिनिधिमंडल में दिनेश शास्त्री और विश्वजीत सिंह नेगी के साथ चमोली से महिपाल सिंह गुसाई, डी. एस. बिष्ट, टिहरी प्रेस क्लब अध्यक्ष शशि भूषण भट्ट, महामंत्री गोविंद सिंह पुंडीर और अन्य लोग मौजूद थे।

‘वैली ऑफ वर्ड्स’ इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ

देहरादून(भारत नमन ब्यूरो)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने मधुबन होटल में ‘वैली ऑफ वर्ड्स’ इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का शुभारंभ किया। दो दिवसीय इस फेस्टिवल में देश-विदेश के अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, कलाकार एवं विचारक भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न सत्रों में अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आधारित भावपूर्ण “शब्द वाणी” प्रस्तुति से हुई, जिसने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन संवाद, विचार और रचनात्मक अभिव्यक्ति को समाज तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि ‘वैली ऑफ वर्ड्स’ के माध्यम से उत्तराखण्ड की समृद्ध कला, संस्कृति और साहित्य को राष्ट्रीय व

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिल रही है। राज्यपाल ने कहा कि हाल के वर्षों में देहरादून में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए उपयोगी चर्चा सत्र और साहित्यिक गतिविधियाँ उपलब्ध कराना आयोजकों की दूरदर्शिता और रचनात्मकता का परिचायक है। राज्यपाल ने कहा कि साहित्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिबिंब है, जो राष्ट्र और समाज के चिंतन को दिशा देता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों और युवाओं में साहित्य और कला के प्रति सजगता, संवेदनशीलता और सृजनशीलता का वातावरण विकसित करें। उन्होंने कहा कि साहित्य के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय



विरासत, इतिहास और संस्कृति को उजागर करना अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने ‘वैली ऑफ वर्ड्स’ के आयोजकों को इस फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं और विश्वास व्यक्त किया कि इस मंच पर होने वाला चिंतन और

मंथन समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान ‘वैली ऑफ वर्ड्स’ के निदेशक डॉ. संजीव चोपड़ा ने फेस्टिवल की रूपरेखा और उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद तरुण बंसल, श्री हेमकुण्ड

साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नरेन्द्रजीत सिंह बिंद्रा, पी जे एस पन्नु, डॉ. राजेन्द्र डोमाल, के. बी. एस सिद्धू, अनूप नौटियाल सहित फेस्टिवल में आए अनेक लेखक, कवि, चिंतक साहित्य प्रेमी भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने बाबा केदार व बंदी विशाल के दर्शन किए



पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण

केदारनाथ धाम (भारत नमन)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए तथा विशेष रूद्राभिषेक पूजन कर विश्व कल्याण, मानवता की स्मृद्धि तथा प्रदेश के सतत विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। अधिशासी अधिकारी डीडीएम विनय झिंकवाण ने राज्यपाल को धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश पुनर्निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य अंतिम चरण में हैं।

राज्यपाल ने मंदिर परिसर में पुरोहित समाज से भेंट की, जिनके

द्वारा राज्यपाल का पारंपरिक मंत्रोच्चारण और पूजा विधि से स्वागत किया गया। राज्यपाल ने केदारनाथ में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों से भेंटकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को सेवा भाव करने कार्य करने को प्रेरित करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इस मौके पर अपरजिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह रावत, मुख्य कार्याधिकारी मंदिर समिति विजय थपलियाल, उपजिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला, अध्यक्ष पं० राजुमार तिवारी, महामंत्री राजेन्द्र तिवारी, मंत्री अंकित प्रसाद सेमवाल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं तीर्थ पुरोहित आदि उपस्थित रहे।

बंदीनाथ में मास्टर प्लान के कार्यों की जानकारी ली

बंदीनाथ (भारत नमन)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने बंदीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बंदी विशाल के दर्शन किए और विशेष पूजा में प्रतिभाग किया। उन्होंने देश और राज्य की स्मृद्धि की कामना की। बंदीनाथ पहुंचने पर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने जिलाधिकारी गौरव कुमार से धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान के कार्यों से अवगत कराया। राज्यपाल ने सिविक एमीनिटी सेंटर, सिविक कम्युनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, हॉस्पिटल बिल्डिंग की प्रगति पर संतोष जताया और मास्टर प्लान के कार्यों की

सराहना की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को मास्टर प्लान के कार्यों की प्रगति की फोटो सहित डाक्यूमेंटेशन तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही शेष नेत्र और बंदीनाथ झीलों की सफाई व्यवस्था को सुचारु रखने व आस्था पथ पर लाइट आदि के कार्य को मॉटेन रखने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने चारधाम व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी चन्द्रशेखर वशिष्ठ, पुलिस उपधीक्षक मदन सिंह बिष्ट, बीकेटीसी प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, नगर पंचायत बंदीनाथ के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

छेनागाड़ आपदा में लापता 09 में से 07 व्यक्तियों के शवों की पहचान

रुद्रप्रयाग (भारत नमन ब्यूरो)। जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्रांतर्गत छेनागाड़ में दिनांक 28-29 अगस्त, 2025 की रात्रि को आई भीषण दैवीय आपदा अतिवृष्टि (बादल फटने की घटना) के कारण नौ (09) लोग, जिनमें चार (04) नेपाली मूल के व्यक्ति भी सम्मिलित थे, लापता हो गए थे। घटना के उपरांत से ही जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, डी.डी.आर.एफ. एवं अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा लगातार सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। आपदा की गंभीरता एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक टीमों निरंतर अथक प्रयासों में जुटी हुई हैं।

इन्हीं सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक कुल सात (07) शव अवशेष बरामद किए जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी ऊखीमठ के कार्मिकों द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र में दो शव दिखाई देने की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही डी.डी.आर.एफ. टीम बसुकेदार तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनों शवों को सर्च ऑपरेशन के तहत बरामद कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। इसके उपरांत चलाए गए सघन सर्च अभियान के दौरान पांच (05) अन्य शव अवशेष बरामद किए गए। इस प्रकार अब तक कुल सात (07) व्यक्तियों के शव बरामद हो चुके हैं।

बरामद शवों में से एक व्यक्ति की पहचान कुलदीप सिंह नेगी, पुत्र बीरबल सिंह नेगी, निवासी ग्राम उछोला (भोर), थाना गुप्तकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, आयु 25 वर्ष, व्यवसाय वन श्रमिक, के रूप में परिजनों द्वारा की गई है। शेष बरामद शवों की शिनाख्त प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आवश्यक पंचनामा एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ से ही आपदा प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सर्च एवं रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मलबे की गहराई को देखते हुए प्रशासनिक टीमों ने बड़े बोल्टों पर ब्लास्टिंग कर सर्च कार्य को गति दी गई है।

पहाड की आर्थिकी को नया संबल दे रही बबाई की रुपदेई

रुद्रप्रयाग (भारत नमन)। जनपद के ग्राम बबाई की श्रीमती रुपदेई देवी ने अपनी मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। एकता स्वयं सहायता समूह एवं उन्नति स्वायत्त सहकारिता नारी की सदस्य रुपदेई का चयन ग्रामोत्थान परियोजना रुद्रप्रयाग के मानकों के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यम के रूप में किया गया है।

परियोजना के तहत उन्हें 30 हजार रुपए की सहायता राशि, 50 हजार का बैंक लोन तथा 20 हजार रुपए का लाभार्थी अंश प्रदान किया गया जिसके माध्यम से उन्होंने बकरी पालन शुरू किया। वर्तमान में रुपदेई के पास 25

बकरियां हैं और यह उनके परिवार की आजीविका का मजबूत आधार बन चुका है। उनकी मेहनत और समर्पण ने केवल आत्मनिर्भर भारत के सपने का साकार कर रहा है बल्कि यह भी साबित करता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी पालन आज भी आर्थिकी का प्रमुख सशक्त साधन है। रुपदेई अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही हैं।

मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि बकरी पालन पर्वतीय क्षेत्र में एक पारम्परिक व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके।



यूपीसीएल एवं गेल

देहरादून (भारत नमन)। जिलाधिकारी सविन बसल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की विभिन्न मार्गों पर रोड़ कटिंग की अनुमति तथा मोबाईल टावर लगाए जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। आज यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए, एडीबी आदि के प्रस्ताव बैठक में रखे, जिनपर सशर्त अनुमति दी गई। रात्रि 10 बजे से सुबह 06 तक ही कार्य अनुमति होगी तथा यह अनुमतियां 10 नवम्बर के उपरान्त ही जारी की जाएगीं। कार्य समाप्ति के उपरान्त सड़क को समतल कर चलने योग्य बनाना होगा जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोगिता बिजली लाइन, पेयजल,

एडीबी, यूयूएसडीए

सीवरेज, गैस पाइपलाइन भूमिगत करने के लिए रात को सड़क खोदने की अनुमति अवश्य दी जा रही है, किंतु इन सभी कार्यों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। मानको का उल्लंघन तथा अनुमति से अधिक रोड़ कटिंग, सड़क खुदी छोड़ना, कार्यस्थल पर बैरिकेडिंग सुरक्षा के इंतजाम की अनदेखी पर जल्दी व मुकदमे से जिला प्रशासन को किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संस्थानों से एनओसी एवं कटिंग चार्ज जारी रखने के उपरान्त ही अनुमति जारी की जाएगी। जिलाधिकारी ने यूपीसीएल एवं अन्य एजेंसियों का पर्यवेक्षण-देखरेख ठीक न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए

कार्यों की उप जिलाधिकारी को साईट

सुपरविजन सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम, बैरिकेडिंग, आदि समुचित इंतजाम करने होंगे। उन्होंने निर्देश दिए संचालित निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण एवं देखरेख स्वयं करेंगे तथा अपने ठेकेदार को निर्देशित करेंगे। जिला प्रशासन की क्यूआरटी निरीक्षण में मानकों का उल्लंघन एवं लापरवाही पाए जाने पर विधिक एक्शन लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों की होगी। उन्होंने कहा कि देख जा रहा है निर्माण कार्यों की खुदाई के दौरान स्मार्ट सिटी के विभिन्न उपकरणों कैमरो को नुकसान पहुंच रहा है। संस्थाओं को

स्मार्ट सिटी से भी एनओसी के उपरान्त कार्यों की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी को यूपीसीएल एवं गेल एडीबी, यूयूएसडीए के कार्यों की साईट विजिट के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेयजल निगम एवं अन्य समस्त कार्यदायी संस्था अपने निर्माण कार्यों की अनुमति के साथ डंपिंग जोन की स्थिति भी स्पष्ट रूप से वर्णित करेंगे। साथ जो भी कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों हेतु अनुमति हेतु आवेदन कर रही हैं वे पूर्ण जानकारी एवं कार्यों निर्धारित समयावधि का उल्लेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण के तत्काल बाद सड़क

विजिट के निर्देश

को करना होगा सुव्यवस्थित तथा सड़क खुदाई की अनुमति से पूर्व जमा करनी होगी सड़क ठीक कराने की धनराशि। साथ ही पुराने कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी। निर्माण साईटों पर कार्यदायी संस्थाओं को मौके पर रखने होगा अपना कार्मिक। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लि0 तीरथपाल सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि ओमपाल सिंह, यूपीसीएल, एडीबी, यूयूएसडीए, रिलाईंस जियो, गेल, वोडाफोन आदि कम्पनियों के प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनपद में 3 से 9 नवम्बर तक उत्तराखंड रजत जयंती सप्ताह

तैयारियों को लेकर डीएम की खास बैठक, कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तय

देहरादून (भारत नमन ब्यूरो)। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के परिपेक्ष्य में जनपद भर में 3 से 9 नवम्बर तक रजत जयंती सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह और स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रजत जयंती सप्ताह में जिला मुख्यालय, ब्लाक एवं तहसीलों में प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करते हुए जन सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर नारी शक्ति दिवस, सुशासन दिवस, यूथ स्पोर्ट्स पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, शहीदों को नमन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, रोजगार दिवस, स्वदेशी खादय, विकास का सफर आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित

प्रतिदिन अलग-अलग थीम के साथ पूरे जनपद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला मुख्यालय, ब्लाक और तहसील स्तरों पर होने वाले कार्यक्रमों की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नारी शक्ति दिवस पर स्वयं सहायता समूह व एनआर एलएम समूह द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगायी जाए। सुशासन दिवस पर प्रत्येक ब्लाक स्तर पर वृहद बहुउद्देशीय शिविर लगाकर जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए। युवा दिवस पर क्रासकन्ट्री रेस, पैराग्लाइडिंग, हॉट बैलून सहित अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। लोगों को बैंकिंग की जानकारी देने के लिए आरबीआई की वर्कशॉप आयोजित की जाए। नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रति वृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं। सभी ऐतिहासिक एवं



सांस्कृतिक धरोहरों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हुए अमर शहीदों के बलिदान एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाए। जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थाओं में विजन-2050 विषय

पर गोष्ठी निबंध, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, सीएमओ डा. मनोज कुमार

शर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर धिल्लियाल सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के सुशील चमोली विज्ञापन मान्यता समिति के सदस्य



मान्यता समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। महासंघ ने इस नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया है। महासंघ के केन्द्रीय अध्यक्ष निशीथ सकलानी व अन्य पदाधिरियों, सदस्यों ने सुशील चमोली को शुभकामनाएं दी हैं।

आपको बता दें कि सरकार ने प्रदेश में समाचार पत्रों की विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के लिए गठित सूचीबद्धता

समिति में मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर चार सदस्यों में अनुपम त्रिवेदी, जय सिंह रावत, रवि बीएस नेगी और चन्द्रशेखर बुडाकोटी को नामित किया गया। इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद से सम्बद्ध संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस -एन-मीडियामैन से दीन दयाल मित्तल और आल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन से सोमपाल सिंह को नामित किया गया है। उत्तराखंड श्रम विभाग से पंजीकृत संगठनों में उत्तराखंड पत्रकार महासंघ से सुशील चमोली और जर्नलिस्ट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड से गिरीश पंत को विज्ञापन सूचीबद्धता संचालन समिति में नामित किया गया है।

देहरादून (भारत नमन)। भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सांसद राज्यसभा डा. नरेश बंसल ने इस वर्ष की योजना में नय सांसद आदर्श ग्राम चयन किया है। इसके लिए देहरादून के सहसपुर ब्लाक के हरीयावाला कलां गांव का चयन किया गया है। डा. नरेश बंसल ने अपने नोडल जिले देहरादून के सहसपुर ब्लाक के हरीयावाला कलां गांव का चयन किया है जिसे बतौर सांसद गोद लेकर इस गांव के विकास की रूपरेखा भी तय करने हेतु आपका सेवक आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत जनता मिलन कर समस्या जानने हेतु आज शनिवार डा. नरेश बंसल सभी संबंधित अधिकारीगण के साथ गांव हरीयावाला पहुंचे व उपस्थित जनप्रतिनिधि

गण व गांव के निवासीयो से समस्याएं जानी व विकास हेतु सुझाव मांगे जिसके तहत गांव के विकास का प्लान अधिकारीगण के साथ बैठक में तय किया जाएगा। ग्राम व्यवस्था को भी सशक्त किया जा सकेगा। डा. नरेश बंसल ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि उक्त ग्राम पंचायत की कार्य योजना डीआरडीए में उपस्थित होकर पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद गांव को समग्र योजना से आच्छादित करने के अभियान में जुटेंगे। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

महाराजा रणवीर सिंह चौक के लिए पार्षदों का समर्थन जुटाएगी रोहिला परिषद

देहरादून (भारत नमन)। अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद देहरादून शाखा की आम सभा अध्यक्ष प्रदीप रोहिला की अध्यक्षता में राजेन्द्र नगर स्थित संकीर्तन भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही तय हुआ कि देहरादून में महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के नाम पर चौक के लिए परिषद के पदाधिकारी और सदस्य पार्षदों का समर्थन लेने के लिए उनसे भेंट करेंगे। आम सभा में सदस्यों को जानकारी दी गयी कि परिषद ने देहरादून में किसी एक चौक का नामकरण रोहिला क्षत्रियों के गौरव और सनातन धर्म रक्षक महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के नाम पर किए जाने के आग्रह के साथ महापौर सौरभ थपलियाल से भेंट की थी। महापौर ने परिषद के आग्रह से सहमति व्यक्त करते हुए नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस बारे में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया है। परिषद ने विचार किया कि नगर निगम की बोर्ड की बैठक से पूर्व परिषद विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों से सम्पर्क साधेगी और

उनसे इस बारे में समर्थन और सहमति देने का अनुरोध करेगी।

आम सभा में आगामी जनगणना में परिषद की केन्द्रीय कमेटी के निर्देशानुसार से सभी जाति वाले कालम में रोहिला क्षत्रिय लिखने की अपील की गयी। बैठक में परिषद द्वारा स्थापित आपदा राहत कोष का सदस्य बनने का आग्रह भी सदस्यों से किया गया जिससे आपात स्थिति में जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जा सके। कोषाध्यक्ष विनोद रोहिला ने आडिट रिपोर्ट पढ़कर बतायी और आय व्यय की जानकारी आम सभा को दी इससे पहले रोहिलखंड गौरव महाराजा रणवीर सिंह रोहिला का 822 वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर और पुष्प चढ़ाकर स्मरण किया गया। नरेश रोहिला ने महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला और बताया कि कैसे महाराजा रणवीर सिंह रोहिला ने जीवन पर्यन्त आक्रांताओं से संघर्ष किया और हिन्दुशाही तथा सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान

दिया। अन्त में परिषद के देहरादून अध्यक्ष प्रदीप रोहिला ने सभी का आभार प्रकट किया। संचालन सचिव राजकुमार रोहिला ने किया।

बैठक में अध्यक्ष प्रदीप रोहिला, सचिव राजुमार रोहिला, कोषाध्यक्ष विनोद रोहिला, महिला समिति की संयोजिका

राजबाला, दिलबाग सिंह रोहिला, सत्यपाल रोहिला, सुधीर, अनिल रोहिला, प्रताप सिंह, मोनिका, गीता, पूजा, रेनू विक्रम चिकारा, अरविन्द रोहिला, अरुण, गोपाल रोहिला, आशीष, शशिकांत, नलिनेश, रजनीश, महेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।



भारत नमन भारत नमन

सम्पादक :
नरेश रोहिला
सलाहकार सम्पादक
देवेन्द्र चौहान,
वीर सिंह
कानूनी सलाहकार
अनुराग रोहिला

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक नरेश रोहिला द्वारा दिशा ग्राफिक्स प्रिंटर्स 43, ओंकार रोड, चूकखुवाला, ब्लॉक-11, देहरादून, उत्तराखण्ड से मुद्रित कराकर कार्यालय ई-210 केदारपुरम, एमडीडीए कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड से प्रकाशित।

सम्पादक: नरेश रोहिला
मो0: 9927258834
RNI No. UTTHIN/2004/15552
हरिद्वार कार्यालय :
हाउस नं0-823,
मौहल्ला-दादूबाग, सर्वप्रिय विहार
कालोनी (लास्ट) हरिद्वार।
फोन नं.: 01334-244353

नोट-समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों हेतु देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा। समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक हैं।